गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 182
दि. 03.11.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

भारत की बेटियों का सुनहरा इतिहास: पहली बार महिला विश्व कप जीता, मैदान पर गूंजी 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' की गूंज

टूटे सपनों से नई सुबह तक

(जीएनएस)। नवी मुंबई। रविवार की रात जब डी.वाई. पाटिल स्टेडियम का आसमान आतिशबाज़ी से जगमगाया और हर तरफ तिरंगा लहराने लगा, तब भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया था। दो दशक का लंबा इंतजार, 2005 और 2017 की अधूरी कहानियाँ, टूटी उम्मीदें और भरे गले – सबकुछ उस पल के साथ मिट गया, जब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। यह जीत केवल एक मैच नहीं थी — यह वह भावनात्मक विस्फोट थी जिसमें वर्षों की मेहनत, आँसू और आत्मविश्वास का संगम था। जब हरमनप्रीत ने आखिरी कैच पकड़कर दोनों बाहें आसमान की ओर उठाईं, तब उनकी आंखों से बहते आँसू करोड़ों भारतीयों की आंखों से मिल गए। दो दशक से टूटी उम्मीदें अब गर्व की मुस्कान में बदल चुकी थीं।

भारत की यह यात्रा आसान नहीं थी। 2005 में सेंचुरियन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की करेन रोल्टन ने भारतीय सपनों को शतक के साथ तोड़ दिया था। 2017 में लॉर्ड्स में अन्या श्रुबसोल की छह विकेटों की जादुई गेंदबाजी ने लाखों दिलों को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन 2025 में कहानी बदल गई। इस बार शेफाली वर्मा की आक्रामकता, दीप्ति शर्मा का संतुलन, हरमनप्रीत कौर की रणनीति और पूरी टीम का जज्बा — सबने मिलकर उस मुकाम को छुआ, जहां से भारतीय महिला क्रिकेट ने दुनिया को झुकाकर रख दिया। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने 17.4 ओवर में 104 रनों की साझेदारी की, जो इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। मंधाना ने 45 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि शेफाली ने 84 गेंदों में 87 रन बनाकर विरोधी गेंदबाजों को असहाय कर दिया। बारिश से बाधित हुई पारी के बावजूद भारत ने सात विकेट पर 298 रन बनाए — यह विश्व कप फाइनल के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। दीप्ति शर्मा ने 55 रन जोड़कर अंत में टीम को ठोस स्थिति में पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने अकेले संघर्ष करते हुए 98 गेंदों पर 101 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने बाकी बल्लेबाज टिक नहीं सके। अमनजोत कौर के डायरेक्ट थ्रो ने ब्रिट्स को रन आउट किया, फिर शेफाली ने 'गोल्डन आर्म गर्ल' बनकर सुने लुस और मारिजाने कैप को आउट किया। मैच का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब दीप्ति शर्मा ने अपने अनुभव और सटीकता से खेल का पूरा रुख पलट दिया। उन्होंने 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया और महिला विश्व कप फाइनल में पाँच विकेट लेने वाली पहली स्पिनर बनीं। वोल्वार्ड्ट के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमर टूट गई। क्लो ट्रायोन और डी क्लार्क ने संघर्ष किया, लेकिन दीप्ति ने डी क्लार्क को आउट कर मैच भारत की झोली में डाल दिया। स्टेडियम में गूंज उठे नारे — "भारत की बेटियाँ ज़िंदाबाद!"

प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत! फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा था। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने असाधारण टीमवर्क और दृढ़ता दिखाई। यह ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।

अमित शाह बोले — यह भारत का गौरवशाली क्षण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, विश्व चैंपियन टीम इंडिया को सलाम! यह देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है। हमारी बेटियों ने ICC महिला विश्व कप 2025 जीतकर भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। यह जीत लाखों लड़कियों को अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेगी। पूरी टीम को हार्दिक बधाई। यह जीत सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के सुनहरे युग की शुरुआत है। इन बेटियों ने साबित कर दिया कि जब हिम्मत, मेहनत और जुनून एक साथ चलते हैं, तो इतिहास लिखा जाता है — और आज भारत ने इतिहास लिख दिया है।

'अब हम विश्व चैंपियन हैं'

आखिरी प्रस्तुति के दौरान हरमनप्रीत ने ट्रॉफी उठाई और कहा — "यह जीत केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए है जिसने अपने सपनों के लिए समाज से लड़ाई लड़ी। हमने आज दिखा दिया कि बेटियाँ किसी से कम नहीं।" नवी मुंबई की रात आतिशबाज़ी की चमक में डूबी थी। भारत के हर घर में जश्न था। सड़कों पर नाचते लोग, सोशल मीडिया पर तिरंगे इमोजी और हर दिल में एक ही गर्व भरा स्वर — "हम विश्व चैंपियन हैं!" इस जीत ने महिला क्रिकेट के इतिहास को नई दिशा दी है। यह सिर्फ एक खेल नहीं रहा — यह भारत की बेटियों की कहानी है जिन्होंने अपने पसीने और आत्मविश्वास से इतिहास लिखा। 2005 और 2017 की हार अब अतीत बन चुकी है। 2025 का यह साल अब सदा कहा जाएगा — "जब भारत की बेटियाँ दुनिया की चैंपियन बनीं।"

भावनाओं का विस्फोट — जब सपने सच हुए

जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, हरमनप्रीत कौर घुटनों पर बैठ गईं, सिर आसमान की ओर उठाया और खुशी के आँसुओं के साथ दहाड़ उठीं। यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस भारतीय लड़की की थी जिसने कभी बल्ला उठाकर मैदान पर अपने सपनों को जगह देने की कोशिश की थी। गैलरी में बैठे रोहित शर्मा ने खड़े होकर तालियाँ बजाईं — वही रोहित, जो 2023 पुरुष विश्व कप फाइनल में हार के दर्द से गुज़रे थे। इस बार उनकी आंखों में सुकून था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट ने अपना सूखा खत्म कर दिया था। सचिन तेंदुलकर, मिताली राज, और झूलन गोस्वामी भी मैदान पर मौजूद थीं — सभी ने बेटियों को झुककर सलाम किया।

देश में घट रहा नक्सलवाद का प्रभाव: अब सिर्फ 38 जिले हिंसा से प्रभावित, सरकार की सख्त नीति से बदला परिदृश्य

(जीएनएस)। नई दिल्ली। एक समय था जब नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। केंद्र सरकार की लगातार सख्त कार्रवाई, सटीक रणनीति और विकास केंद्रित नीतियों के चलते नक्सलवाद का दायरा तेजी से सिमट रहा है। गृह मंत्रालय की ताजा समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अब देश में नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 38 रह गई है। जबकि इसी वर्ष अप्रैल तक नौ राज्यों में कुल 46 जिले माओवादी गतिविधियों से प्रभावित थे।

यह रिपोर्ट 'वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism - LWE) से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015' के अंतर्गत की गई समीक्षा का हिस्सा है। इस नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा, विकास और पुनर्वास – तीनों मोर्चों पर

समानांतर काम कर रही हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश में नक्सल हिंसा में पिछले एक दशक के भीतर 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है और अब नक्सलवाद कुछ गिने-चुने जिलों तक सीमित रह गया है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में केवल चार जिले ऐसे हैं जिन्हें "चिंताजनक" श्रेणी में रखा गया है, जहां माओवादी संगठन अब भी सक्रिय रूप से चुनौती दे रहे हैं। वहीं, तीन जिले "अत्यधिक प्रभावित" श्रेणी में हैं, जहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच समय-समय पर मुठभेड़ की घटनाएं होती हैं। बाकी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है और अधिकांश क्षेत्रों में माओवादी संगठन या तो निष्क्रिय हो चुके हैं या फिर सरेंडर की प्रक्रिया के तहत सामने आ चुके हैं।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा अब भी नक्सलवाद के अवशेषों से जूझ रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में भी नक्सलियों की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। जहां पहले छत्तीसगढ़ का बस्तर और सुकमा ज़ोन माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, वहीं अब वहां सड़कों का निर्माण, बिजलीकरण, और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचने लगी हैं।

सरकार की रणनीति अब सिर्फ सुरक्षा अभियानों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास और विश्वास दोनों को साथ लेकर चलने की दिशा में केंद्रित है।

गोवा में अवैध रेत खनन पर मचा बवाल : गोलीबारी में दो घायल, दो पुलिसकर्मियों समेत सात आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)। पणजी। गोवा के शांत तटों और पर्यटन स्थलों के बीच अब अवैध रेत खनन ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। उत्तरी गोवा के परनेम इलाके में रेत खनन को लेकर हुई गोलीबारी ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को हिला दिया है। इस घटना में दो व्यक्तियों को गोली लगी, जबकि पुलिस ने इस मामले में दो पुलिसकर्मियों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह वारदात 28 अक्तूबर की रात लगभग 2:30 बजे की है, जब खारने (पोरस्कोडेम) निवासी रामऋषि पासवान अपने साथी लालबाबू गोड के साथ तेरेखोल नदी के किनारे से रेत निकाल रहे थे। तभी वहां पहुंचे कुछ लोगों ने उन पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में रामऋषि पासवान की गर्दन में गोली लगी, जबकि लालबाबू गोड को दाहिने हाथ और पेट के पास गोली लगी। घायल दोनों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह गोलीबारी अवैध रेत खनन के नियंत्रण को लेकर हुए विवाद का नतीजा थी। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पिछले कई महीनों से तेरेखोल नदी के किनारे अवैध रेत निकासी का कारोबार तेजी से बढ़ा है, जिसमें स्थानीय माफिया, ट्रक मालिकों और कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं। उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है। अब तक की कार्रवाई में दो पुलिस कांस्टेबलों सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वे रेत माफिया को संरक्षण दे रहे थे और घटना की रात वहां मौजूद थे। एसपी गुप्ता ने कहा, "अवैध रेत खनन गोवा में एक गंभीर पर्यावरणीय और कानून व्यवस्था का मुद्दा बनता जा रहा है।

देश के उभरते तीरंदाज अर्जुन सोनावणे की ट्रेन हादसे में दर्दनाक मौत, खेल जगत में शोक की लहर

(जीएनएस)। कोटा। देश के खेल जगत के लिए शनिवार की रात एक दिल दहला देने वाली खबर लेकर आई। महाराष्ट्र के उभरते नेशनल तीरंदाज अर्जुन सोनावणे की राजस्थान के कोटा में ट्रेन हादसे में मौत हो गई। महज 21 वर्ष के इस खिलाड़ी की असमय मौत ने न केवल तीरंदाजी जगत बल्कि पूरे खेल समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार, यह हादसा शनिवार देर रात कोटा जंक्शन पर उस समय हुआ, जब अर्जुन अपनी टीम और कोच के साथ बठिंडा से मुंबई जा रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए धीमी हुई थी, और इसी बीच अर्जुन नाश्ता लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। लेकिन ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही उनका पैर फिसल गया और वे ट्रेन के नीचे आ गए। हादसा इतना अचानक हुआ कि साथी खिलाड़ी और कोच कुछ समझ भी नहीं पाए। तुरंत उन्हें गंभीर हालत में कोटा के एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें एक निजी अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर अर्जुन की जान नहीं बचा सके। हादसे की पुष्टि करते हुए जीआरपी कोटा के अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान महाराष्ट्र के नासिक निवासी अर्जुन सोनावणे के रूप में हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर रविवार सुबह परिजनों को सौंप दिया गया। अर्जुन सोनावणे ने बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने हाल ही में जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की ओर से स्वर्ण पदक जीता था और उन्हें अगली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए संभावित सूची में शामिल किया गया था। उनकी प्रतिभा और अनुशासन ने कोचों और टीममेट्स के बीच उन्हें एक आदर्श खिलाड़ी बना दिया था।

कोच रविंद्र मोरे ने गमगीन आवाज़ में बताया, "अर्जुन बेहद मेहनती और शांत स्वभाव का खिलाड़ी था। वह हर अभ्यास सत्र में सबसे पहले आता था और आख़िर तक मैदान में डटा रहता था। उसके अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की पूरी क्षमता थी। यह हादसा हमारे लिए व्यक्तिगत और पेशेवर, दोनों रूप से बड़ा झटका है।"

अर्जुन के परिवार को हादसे की खबर मिलते ही कोटा के लिए रवाना कर दिया गया। नासिक में उनके घर पर मातम पसरा है। पिता सोमनाथ सोनावणे ने फोन पर कहा, "हमने उसे कल ही फोन किया था, वह खुश था। बोला था कि अगली बार गोल्ड मेडल लाऊंगा। हमें नहीं पता था कि वह आख़िरी बार बात कर रहा है।"

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा : खड़े ट्रक से टकराई टूरिस्ट बस 18 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल – मातोड़ा में मचा कोहराम

(जीएनएस)। जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। फलोदी उपखंड के मातोड़ा इलाके में एक टूरिस्ट बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें 18 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और यात्री अंदर ही फंस गए। रातभर चले राहत और बचाव कार्य के बाद शवों को बाहर निकाला गया और घायलों को जोधपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

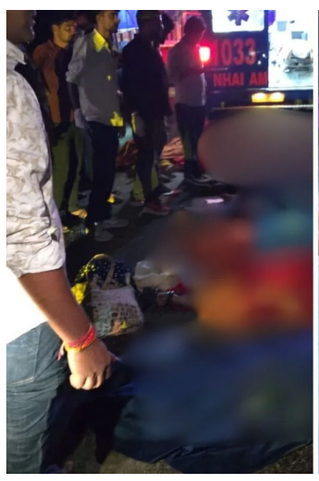

जानकारी के अनुसार, यह बस जोधपुर के सूरसागर इलाके से श्रद्धालुओं का दल लेकर बीकानेर के प्रसिद्ध कोलायत तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुई थी। दर्शन कर लौटते वक्त देर रात लगभग 11 बजे जब बस फलोदी के मातोड़ा क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। अंधेरा और तेज रफ्तार दोनों मिलकर भयावह त्रासदी का कारण बन गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ यात्री बस के अंदर बुरी तरह फंसे थे, जिन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। फलोदी थाने के थाना अधिकारी अमानाराम पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू करवाया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और अन्य साधनों की मदद से बस को काटकर घायलों को बाहर निकाला। कई यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कुछ ने अस्पताल जाते-जाते दम तोड़ दिया। फिलहाल करीब 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3 से 4 लोग गंभीर हालत में जोधपुर के एमजी अस्पताल में भर्ती हैं।

पुलिस के अनुसार, हादसे का प्राथमिक कारण बस चालक की तेज रफ्तार और रात के समय दृश्यता की कमी बताई जा रही है। अंधेरे में चालक को सड़क किनारे खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया और तेज रफ्तार में बस सीधे उसके पिछले हिस्से से जा टकराई। बस में करीब 25 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर परिवार के सदस्य और महिलाएं थीं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस भीषण दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जोधपुर कलेक्टर और जिला प्रशासन को फोन पर तत्काल राहत-बचाव के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के अस्पतालों में तुरंत पहुंचाया जाए ताकि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा मिल सके। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सहायता राशि की घोषणा करने के संकेत भी दिए।

उधर, जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस हादसे पर गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (Twitter) पर लिखा – "फलोदी के मातोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन के संपर्क में हूं। अधिकारियों को तुरंत आवश्यक प्रबंध के निर्देश दिए हैं। जैसा प्रारंभिक विवरण सामने आया है, हादसा अत्यंत दुखद है। हमारी प्राथमिकता घायलों को सर्वोत्तम इलाज दिलाने की है। इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं।" घटनास्थल पर रातभर राहत एवं बचाव अभियान चलता रहा। बस के मलबे में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए गैस कटर की मदद ली गई। आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर मानवता का परिचय दिया और घायलों को अपने वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। कई प्रत्यक्षदर्शियों की आंखें यह दृश्य देखकर भर आईं, जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे को ढूंढते हुए बेसुध हो गए थे।

सोमवार सुबह जब सूरज निकला, तो मातोड़ा का पूरा इलाका मातम में डूबा था। शवों को फलोदी अस्पताल के शवगृह में रखा गया है, जहां मृतकों के परिजनों का सैलाब उमड़ पड़ा। जोधपुर से उच्च अधिकारी और चिकित्सा टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है।

राजस्थान पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश में आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

यह हादसा न केवल जोधपुर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर चेतावनी है कि तेज रफ्तार और लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। सड़क पर खड़ी भारी वाहन और रात में खराब दृश्यता का संयोजन कई बार मौत का कारण बन जाता है। मातोड़ा हादसा भी ऐसी ही दर्दनाक कहानी बन गया, जिसने 18 परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया।

रविवार की यह रात जोधपुर और आसपास के जिलों के लिए हमेशा यादगार रहेगी – एक ऐसी रात जिसने श्रद्धा की यात्रा को शोक यात्रा में बदल दिया।

संपादकीय

विश्व वर्चस्व की दहलीज

भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा सात बार की विश्व चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को हराना महज एक मैच की जीत नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में युगांतरकारी घटना है। कौशल तथा तकनीकी दृष्टि से कठिन यह मुकाबला हार की हैट्रिक लगा कर आ रही भारतीय टीम की मानसिक मजबूती और उसके समन्वय का कड़ा इम्तिहान था। यह मैच फाइनल से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पिछले दस वर्षों में खेले गए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 75 प्रतिशत से अधिक जीत प्रतिशत बनाए रखने वाली ऑस्ट्रेलिया को हराना, महिला क्रिकेट में लगभग 'असंभव' माना जाता है। हालांकि यह भारत ही है, जिसने उसे कई बार टक्कर दी है और विश्व कप के सेमीफाइनल में पहले भी हराया है।

2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ओवर तक चुनौती दी थी, जबकि 2023 की बाइलैटरल सीरीज में भारत ने उन्हें सुपर ओवर में हराकर इतिहास रचा था। इस विजय से साफ है कि भारतीय महिला क्रिकेट ने खुद को दुनिया की शीर्ष चार टीमों, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की कतार में दृढ़ता से स्थापित कर लिया है। भारतीय टीम केवल प्रतिस्पर्धी नहीं, विजेता मानसिकता वाली टीम बन चुकी है। भारत ने पिछले पांच वर्षों में टी-20 और वनडे दोनों प्रारूपों में लगभग 63 प्रतिशत मुकाबले जीते हैं। यह किसी भी उभरती क्रिकेट शक्ति के लिए शानदार रिकॉर्ड है।

बल्लेबाजी में निरंतर सुधार इसका सबसे बड़ा आधार है। नमूने के बतौर स्मृति मंधाना ने पिछले 24 महीनों में 42.7 के औसत से रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर रखा है। हरमनप्रीत महिला क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ बैटर में शुमार हैं। जेमिमा ने अभी शानदार शतक बनाया, तो शेफाली वर्मा और रिचा घोष जैसी निरंतर आक्रामकता महिला क्रिकेट में दुर्लभ है। गेंदबाजी में भी भारत ने प्रभावी प्रगति की है। रेनुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा ने इस क्षेत्र में कई कीर्तिमानी कारनामे अंजाम दिए हैं, हालांकि 'डेथ ओवर्स' की गेंदबाजी और स्पिन विकल्पों में और गहराई लाने की ज़रूरत है।

कई बार शुरुआती सफलता को हमारे गेंदबाजों ने अपने भोथरे आक्रमण से गंवा दिया है। फिलहाल टीम की सबसे बड़ी चुनौती निचले क्रम की बैटिंग और फील्डिंग है। निचले क्रम की बैटर्स का औसत सिर्फ 11.2 रन प्रति खिलाड़ी है, जो ऑस्ट्रेलिया की 17.6 और इंग्लैंड की 15.8 से बहुत पीछे है। हमारा कैच ड्रॉप प्रतिशत 12 के आसपास है। संसार की ऊपरी पायदान वाली टीमों में सबसे अधिक। इन दोनों क्षेत्रों में सुधार अत्यंत आवश्यक है, हालांकि इधर यह टीम न केवल खेल तकनीकी बल्कि मानसिक दृढ़ता में भी मजबूत हुई है।

यह वही आत्मविश्वास है, जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी अजेय टीम को किस्मत से नहीं बाकायदा अपने खेल से मात दी। इसे देख लगता है भारतीय महिला टीम क्रिकेट के स्वर्ण युग की दहलीज पर है। बल्लेबाजी की निरंतरता, गेंदबाजी की धार और फील्डिंग की सटीकता को संयम और समन्वय के साथ बरकरार रखा गया, तो वह निकट भविष्य में ऐसी टीम बन सकती है, जिसे क्रिकेट के तीनों प्रारूपों- टेस्ट, वनडे और टी-20 में हराना लगभग असंभव होगा।

घातक होगा दबाव में विदेशी खाद्यान्न हेतु बाजार खोलना

> "भारत को उन दिनों में वापस नहीं जाने दिया जा सकता जब देश का पेट भरने के लिए खाद्यान्न समुद्री जहाजों से आया करता था। भूख से आजादी सुनिश्चित करने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, और वह भी किसी...

भारत को उन दिनों में वापस नहीं जाने दिया जा सकता जब देश का पेट भरने के लिए खाद्यान्न समुद्री जहाजों से आया करता था। भूख से आज़ादी सुनिश्चित करने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, और वह भी किसी भी कीमत पर।

ऐसे समय में जब अन्न फसलें – गेहूं और धान– की खेती अभी भी अपना वजूद बनाए हुए हैं, शेष लगभग सभी प्रमुख फसलों की चमक फीकी पड़ गई है। चाहे वह दालें हों, तिलहन (सोयाबीन सहित), कपास और मक्का, इनकी कीमतें तेजी से गिर रही हैं। खतरे की घंटियां इससे पहले इतनी ज़ोर से कभी नहीं बजीं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में बर्लिन ग्लोबल डायलॉग को संबोधित करते हुए हिम्मत भरा रुख दिखाया है कि भारत 'सिर पर बंदूक तनवाकर' सौदे नहीं करता।

इस मुश्किल समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहे गए ये साहसी शब्द मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जब तत्कालीन कृषि मंत्री जगजीवन राम रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्यालय में एक बैठक से गुस्से में बाहर निकल गए थे। यदि मैं उस वक्त के कृषि सचिव डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने मुझसे जो कहा था, उसे सही ढंग से बता पाऊं, तो उन्होंने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी से कहा, 'भाड़ में जाए तुम और तुम्हारी हमें कृषि निर्यात बेचने की नीयत' और आगे कहा : भारत कभी भी अमेरिका से खाद्यान्न आयात नहीं करेगा।' जगजीवन राम 1974 से 1977 तक कृषि एवं सिंचाई मंत्री रहे थे। यह स्वामीनाथन का जवाब था, जब मैंने उनसे पूछा कि आजादी के बाद से लगभग सभी कृषि मंत्रियों के साथ विभिन्न पदों पर काम करने का सौभाग्य मिलने के बाद उन्हें कौन-सा कृषि मंत्री

सबसे अच्छा लगा।

इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका हमेशा से विशाल भारतीय कृषि बाजार में पैर जमाने की हसरत रखता आया है। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में कृषि उत्पादों के लिए प्रवेश पाना असल में अमेरिका की विदेश नीति की एक बड़ी इच्छा रही है। ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन हाल ही में, जब ट्रंप का धक्केशाही वाले और सनकी तरीके से टैरिफ लगाना देशों को नई विश्व व्यवस्था अपनाने को मजबूर कर रहा है, भारत ने चल रही अमेरिका-भारत व्यापार वार्ताओं में अब तो अपनी कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। लेकिन मजबूत घरेलू लॉबियां जो सदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के साथ खड़ी रहती हैं और वह भी आत्मनिर्भरता के नाम पर, एक बार फिर सक्रिय हो उठी हैं।

अमेरिका के साथ कपास, सोयाबीन, मक्का, डेयरी, सेब और अन्य स्टोन फ्रूट्स के लिए भारतीय आयात खोलने की जिस दलील को सबके लिए जीत वाला 'रणनीतिक' व्यापार सौदा बताया जा रहा है, उसमें घरेलू हकीकतों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अगला लक्ष्य ज़ाहिर तौर पर चावल होगा, उसके बाद गेहूं, जिसमें अमेरिका का असली हित छिपा है। नीति आयोग ने पहले ही एक वर्किंग पेपर वापस ले लिया है, जिसमें विवादित जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) सेब, मक्का और सोयाबीन को प्रवेश देने का मसौदा था, लेकिन कुछ दूसरे मुख्यधारा के अर्थशास्त्री भी हैं जो कपास पर ज़ीरो ड्यूटी इंपोर्ट की तरह दूध एवं दुग्ध प्रोडक्ट्स के लिए भी भारतीय बाजार खोलने को सही मानते हैं। बिना यह अहसास किए कि अमेरिका में उगाने वाले किसान लगभग 8,000 हैं, जिनके खेतों का औसत आकार 600 हेक्टेयर है,उन्हें आज भी सालाना 100,000 डॉलर से ज़्यादा की सब्सिडी मिलती है। इससे इनकी अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से विकासशील देशों के किसानों को नुकसान होता है। वहीं दूसरी ओर, भारत में 98 लाख कपास उगाने वाले किसान हैं, जिनके पास औसतन 1 से 3 एकड़ के खेत हैं। सस्ते और सब्सिडी पाए आयात से उनकी जो भी थोड़ी-बहुत कमाई है, वह भी छिन जाएगी। अगर घरेलू कपास उद्योग इसकी बजाय हमारे किसानों के साथ खड़ा हो जाए, तब यह सच में एक 'विन-विन सिचुएशन' है। आयात शुल्क को शून्य करके, भारत ने स्वेच्छा से अपने किसानों को भेड़ियों के आगे डाल दिया है।

बात जब दालों की की जाए, तो मांग एवं पूर्ति वाला समीकरण काम करता दिखाई नहीं देता। पिछले पांच सालों में, दालों की खेती का रकबा काफी कम हो गया है, जो कि 30.7 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 27.6 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादा मांग के बावजूद; किसानों को मंडी में मिलने वाली कीमतें बढ़ी नहीं हैं। हकीकत यह है, मौजूदा कीमतें घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से लगभग 30 प्रतिशत कम हैं। उत्पादन में कमी को सस्ते आयात से पूरा किया जा रहा है; असल में यह ज़रूरत से दोगुनी मात्रा है, और कई फलीदार दालों (मटर नस्ल) पर आयात शुल्क शून्य है। अकेले 2024-25 में ही 7.6 मिलियन टन दालें आयात की गई हैं। खबरों के मुताबिक, पिछले पांच सालों में यह लगभग चार गुणा हो गया है, जहां 2020-21 में दालों के आयात पर 12,153 करोड़ रुपये खर्च हुए थे वहीं 2024-25 में आयात की मात्रा पहले ही 47,000 करोड़ रुपये को पार कर चुकी है।

खाने के तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के नाम पर, जीएम सोयाबीन इंपोर्ट को सही ठहराना, फिर से एक दिग्भ्रमित कोशिश है। हालांकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सोयाबीन काश्त पट्टी में किसान आश्वस्त कीमत पाने के लिए परेशान हैं, और पंचायत लेवल पर कई ट्रैक्टर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सोयाबीन का मौजूदा मंडी भाव घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये की बजाय 3,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। आश्वस्त कीमत का नदारद रहने (और साथ ही मौसम की मार) के कारण बुवाई रकबे और उत्पादन में गिरावट आ रही है, जीएम सोयाबीन इंपोर्ट की खबरों का कड़ा विरोध हो रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय का हालिया आदेश, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए जाने तक जीएम खाद्यान्न के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी है, एक अन्य रुकावट बनेगा।

यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब अमेरिका ने पहले भी जीएम सोयाबीन आयात के लिए भारत पर दबाव डाला था। नई दिल्ली स्थित फोरम फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी के नेतृत्व में एक अभियान के बाद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) ने आखिरकार भारतीय बंदरगाहों पर आने पर सोयाबीन की श्रेणियों को अलग-अलग करने के लिए कहा था। इसका अमेरिकी निर्यातकर्ताओं (वरिष्ठ यूएसडीए अधिकारियों के समर्थन से) ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन भारत ने घरेलू जीएम नियामक व्यवस्था को दरकिनार कर झुकने से इनकार कर दिया था। यदि आयात किसी भी हाल में ज़रूरी हो जाए तो जीएम सोयाबीन आयात के लिए भी अब यही तरीका अपनाना चाहिए। इसी तरह, मक्का के मामले में भी, मीडिया खबरों के बाद कि आयात शुल्क मौजूदा 50 परसेंट से घटाकर 15-16 प्रतिशत किया जा सकता है, घरेलू कीमतें पहले ही बहुत गिर गई हैं। खबरों के अनुसार 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले, कुछ जगहों पर बाज़ार कीमतें गिरकर 1,100 से 1,200 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गई हैं।

प्रेरणा

तीन रास्ते, एक जीवन: मानव प्रयत्न की तीन दिशाएं और उनके परिणाम का रहस्य

मानव जीवन की यात्रा एक अदृश्य रथ के समान है, जिसके तीन पहिए हैं — विचार, वाणी और कर्म। ये तीनों ही जीवन की दिशा तय करते हैं। हर मनुष्य निरंतर किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त रहता है। वह चाहे सांस ले रहा हो, बोल रहा हो, सोच रहा हो या कर्म कर रहा हो — ये सब उसके प्रयत्न का ही रूप हैं। यही प्रयत्न उसके भाग्य, उसके सुख-दुःख और उसके अनुभवों का निर्धारण करते हैं। प्रयत्न ही वह सेतु है जो व्यक्ति को उसकी नियति से जोड़ता है।

शास्त्रों में कहा गया है कि प्रयत्न के तीन भेद होते हैं — शुभ कर्म, अशुभ कर्म और शुभाशुभ मिश्रित कर्म। यही तीन रास्ते जीवन को तीन दिशाओं में ले जाते हैं। शुभ कर्म वे हैं जो दूसरों के हित, समाज के कल्याण और आत्मशुद्धि के लिए किए जाते हैं। ऐसे कर्मों का फल सदैव सुख, संतोष और उन्नति के रूप में मिलता है। अशुभ कर्म वे हैं जो स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या किसी की हानि के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनसे उत्पन्न फल दुःख, क्लेश, हानि और मानसिक अशांति के रूप में मनुष्य को लौटते हैं। तीसरी श्रेणी है — शुभाशुभ मिश्रित कर्मों की, जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों का संयोग होता है। इनके परिणाम जीवन में कभी सुख तो कभी दुःख के रूप में अनुभव होते हैं। यही कारण है कि मनुष्य के जीवन में कभी आनंद के क्षण आते हैं तो कभी विषाद के।

मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में परतंत्र। वह अपने कर्म का चयन तो कर सकता है, लेकिन उसके परिणाम को अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकता। यह ब्रह्मांड एक सूक्ष्म न्याय व्यवस्था पर आधारित है, जिसे धर्म या ऋत कहा गया है। यह न्याय व्यवस्था प्रत्येक कर्म का लेखा रखती है और समय आने पर उसका प्रतिफल देती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसके किए हुए अच्छे कर्मों का परिणाम क्यों नहीं मिला, तो उसे यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की गति तत्काल नहीं होती, वह नियत समय पर ही फल प्रदान करती है।

गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यही अमर संदेश दिया — "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।" अर्थात, "तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं।" यह वाक्य समूचे जीवन का दर्शन है। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा रखना पाप है, बल्कि यह कि फल पर अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति को कर्म से दूर कर देती है। जब मनुष्य केवल फल की चिंता करता है, तो उसका कर्म दूषित हो जाता है। लेकिन जब वह निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वह स्वयं शुद्ध होता चला जाता है।

प्रयत्न केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वह व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का दर्पण भी है। यदि मन पवित्र है तो कर्म भी पवित्र होंगे, और यदि विचार दूषित हैं तो कर्म भी उसी के अनुरूप बन जाएंगे। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं — "यथा मनः, तथा वचनम्, तथा कर्म।" अर्थात, जैसा मन होगा, वैसी वाणी और वैसा आचरण होगा। इसीलिए प्रयत्न का आरंभ सदैव विचार की शुद्धि से होना चाहिए। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रयत्न का अर्थ केवल भौतिक सफलता नहीं है। प्रयत्न का गूढ़ अर्थ है — आत्मा की उन्नति। जब मनुष्य अपने प्रयत्नों को धर्म, सत्य और कर्तव्य से जोड़ देता है, तब उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। उसके कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और ब्रह्मांड की समरसता में योगदान देने लगते हैं। यही सच्चा शुभ प्रयत्न है। कभी-कभी मनुष्य यह सोचता है कि वह तो हमेशा अच्छा करता है, फिर भी जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं। इसका उत्तर यह है कि जीवन में केवल वर्तमान कर्म ही नहीं, अपितु पूर्व जन्मों के संचित कर्म भी प्रभाव डालते हैं। जो सुख-दुःख हम आज भोग रहे हैं, वे कई जन्मों के कर्मों का संयुक्त परिणाम हैं। लेकिन वर्तमान प्रयत्न के द्वारा हम भविष्य को अवश्य बदल सकते हैं। यही प्रयत्न का चमत्कार है।

संत-महात्मा कहते हैं कि कर्म करना ही जीवन का धर्म है। यदि मनुष्य केवल ज्ञान सुनता रहे, लेकिन उसके अनुसार प्रयत्न न करे, तो वह केवल श्रोता रह जाता है, साधक नहीं बन पाता। जैसे कोई व्यक्ति दवा का नाम जानता है पर उसे खाता नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति कर्म का उपदेश तो सुनता है पर उसे अपनाता नहीं, वह रोगी ही बना रहता है। इसलिए केवल सुनने से नहीं, बल्कि कर्म के माध्यम से ही मुक्ति और कल्याण संभव है।

जीवन के तीन रास्ते हमारे सामने हर दिन उपस्थित रहते हैं — एक जो शुभता की ओर ले जाता है, दूसरा जो अशुभता की ओर गिराता है, और तीसरा जो अनुभव के माध्यम से शिक्षा देता है। हमें यह तय करना होता है कि हम किस दिशा में अपने प्रयत्नों को मोड़ते हैं। यदि हमारे विचारों में करुणा है, वाणी में मधुरता है और कर्मों में निःस्वार्थ भाव है, तो जीवन स्वयं ही प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है।

अंततः प्रयत्न ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सामान्य से असामान्य बनाती है। कर्म ही उसकी सच्ची पहचान है। फल चाहे जैसा भी मिले, किंतु कर्म की निष्ठा ही उसे ईश्वर के समीप ले जाती है। इसलिए कहा गया है — "कर्म ही पूजा है।" जो व्यक्ति अपने जीवन को इस सत्य के आधार पर चलाता है, उसके लिए हर रास्ता अंततः मुक्ति की ओर जाता है, क्योंकि तीनों रास्तों में भी सच्चा पथ वही है, जो शुभ कर्म से होकर गुजरता है। यही जीवन का सार है — कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर प्रयत्न का अपना परिणाम है, और हर परिणाम तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही आता है।

'रेवड़ी संस्कृति': लोकतंत्र का आधार या प्रलोभन की डगर?

बिहार की राजनीति एक बार फिर चुनावी रंग में रंग चुकी है। हर चुनावी सभा में, गली-मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक मुफ्त रेवडियों की घोषणाओं और वादों की बाढ़ आई हुई है। यह चुनावी मौसम पहले की तरह इस बार भी 'रेवड़ी संस्कृति' से सराबोर दिखाई देता है। महागठबंधन हो या एनडीए-दोनों गठबंधन एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ऐसे-ऐसे वादे कर रहे हैं जो सुनने में आकर्षक लगते हैं, पर उनकी व्यवहारिकता और आर्थिक सम्भावना पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। ये चुनावी वादें कैसे पूरे होंगे या जनता के साथ विश्वासघात होगा? हर दल मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा रहा है, लेकिन शायद ही किसी ने यह सोचा हो कि इन लोकलुभावन योजनाओं के लिए फंड कहां से आएगा, कैसे उनकी पूर्ति होगी और क्या यह राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति पर और बोझ नहीं बनेगा।बिहार का यह चुनाव इसलिए खास नहीं है क्योंकि इससे दो दशकों से राज्य का चेहरा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भविष्य तय होना है-यह खास इसलिये है क्योंकि दोनों गठबंधनों की तरफ से एक जैसी राजनीति चल रही है-लोकलुभावन घोषणाओं की। महागठबंधन ने दो दिन पहले 'तेजस्वी -संकल्प' घोषित किया। कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों ने बीते दिनों में जो चुनावी वादे किए हैं, उन्हें ही इसमें शामिल किया गया है। दूसरी ओर एनडीए के वादों की लिस्ट भी बेहद लंबी है। शुरुआत में नीतीश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये, 125 यूनिट फ्री बिजली, एक करोड़ नौकरियों का वादा, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, बढ़ी पेंशन-नीतीश ने चुनावी अभियान इस तरह शुरू किया। महागठबंधन ने जवाब में 200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर महीने ढाई हजार, और भी बहुत कुछ देने का वादा किया है। दोनों की गठबंधन की आसमानी घोषणाएं लुभा रही है, जनता को गुमराह कर रही है, सीधे-सीधे रूप में यह वोटों को खरीदने की साजिश है। नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि देश की जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 9 प्रतिशत से ज्यादा है, पर जीडीपी में योगदान 2021-22 में घटकर 2.8 प्रतिशत रह गया। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का केवल 30 प्रतिशत है, जबकि बेरोजगारी ज्यादा है। 2022-23 में राज्य की जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात 39.6 प्रतिशत था। बिहार के सामने सबसे बड़ी समस्या है आय के साधन जुटाने की। कुल कमाई में उसका अपना टैक्स रेवेन्यू केवल 23 प्रतिशत है और केंद्र की तरफ से अनुदान का हिस्सा 21 प्रतिशत। जन सुराज का दावा है कि मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने के लिए 33 हजार करोड़ चाहिए होंगे। इस आंकड़े को सच मान लें तो राज्य के कुल बजट में से रोजमर्रा के कामकाज व योजनाओं का खर्च निकालने के बाद करीब 40 हजार करोड़ रुपये बचते हैं। क्या मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं के वादा इससे पूरे होंगे? एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही एक-दूसरे की घोषणाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हकीकत में दोनों को बताना चाहिए कि वे किस तरह इन वादों को पूरा करेंगे। बेरोजगारों को भत्ता, महिलाओं को नकद सहायता, युवाओं को लैपटॉप, किसानों के लिए ऋणमाफी-इन घोषणाओं की बाढ़ ने लोकतंत्र को मजबूती देने के बजाय उसे लोकलुभावन जाल में फंसा दिया है। यह स्थिति केवल बिहार की नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक नई प्रवृत्ति के रूप में उभर रही है, जहां सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता जनता की विवेकशीलता से नहीं, बल्कि प्रलोभनों की मिठास से तय किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं, क्योंकि यह मतदाता को उपभोक्ता में बदल देती है और राजनीति को नीति से भटकाकर लाभ की गणित में फंसा देती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई 'रेवड़ी संस्कृति' की अवधारणा आज बिहार की राजनीति में पूर्णरूपेण साकार होती दिख रही है। मुफ्त बिजली, राशन, यात्रा या सहायता योजनाएं अब चुनावी घोषणाओं की अनिवार्य शर्त बन गई हैं। जनकल्याण का उद्देश्य पीछे छूट गया है, सामने है तो केवल वोटों की गिनती। इन घोषणाओं के माध्यम से मतदाता को प्रभावित करना एक तरह का सॉफ्ट करप्शन है, जहां खरीदी खुलकर नहीं होती, पर मानसिक रूप से मतदाता को बंधक बना लिया जाता है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है, क्योंकि यह नीतियों और सिद्धांतों को कमजोर करती है और राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का खेल बना देती है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब चुनाव नैतिक और नीति-सम्मत हों। चुनाव का अर्थ केवल जीत और हार नहीं, बल्कि समाज के चरित्र और दिशा का निर्धारण है। नैतिक राजनीति वही है जिसमें जनहित को सर्वोपरि माना जाए, न कि तत्कालिक लाभ को। यदि राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में केवल आकर्षक वादे ही भरते जाएं और उनके पीछे कोई आर्थिक या सामाजिक दृष्टि न हो, तो यह लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। मतदाता को चाहिए कि वह ऐसी घोषणाओं से प्रभावित न हो, बल्कि यह देखे कि कौन-सी पार्टी या नेता दीर्घकालिक सुधार, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन की बात कर रहा है। लोकतंत्र उपहार नहीं, उत्तरदायित्व है, इसे समझना और निभाना नागरिक का धर्म है। वोट किसी के द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता, सुशासन और सच्चे विकास के लिए दिया जाना चाहिए। मतदाता का विवेक ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर जनता भावनाओं या लालच में निर्णय लेगी, तो राजनीति और शासन दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। इसी तरह दलों को भी आत्मसंयम रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सत्ता की प्राप्ति साधन नहीं, सेवा का अवसर है।

अभियान

जीवन में आने वाली बाधाएं कैसे होंगी दूर, जानें इन चमत्कारी उपायों को जो बदल देंगे भाग्य की दिशा

मनुष्य का जीवन सागर की लहरों की तरह है, जिसमें कभी शांति होती है तो कभी तूफान। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख, समृद्धि और सफलता से भरा रहे, परंतु अनेक बार अदृश्य शक्तियाँ, ग्रहों की प्रतिकूल दशाएं, या स्वयं के कर्मों का परिणाम ऐसा जाल बुन देते हैं कि जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। कभी काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, तो कभी बिना किसी कारण घर-परिवार में अशांति छा जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करता है, लेकिन शास्त्रों ने इस स्थिति से बाहर निकलने के उपाय पहले ही बता दिए हैं। जिन उपायों को श्रद्धा, विश्वास और नियमितता से अपनाया जाए, वे व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं।

कहा गया है कि जब ग्रह अनुकूल नहीं होते, तब सबसे पहले मनुष्य की एकाग्रता और निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। जब मन विचलित होता है तो कर्म भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को सबसे बड़ा उपाय बताया गया है।

प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान गणेश का स्मरण करना, जीवन की हर विघ्न-बाधा को दूर करने का प्रथम कदम माना गया है। गणपति को दुर्वा घास अर्पित करते हुए यदि व्यक्ति "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करे, तो उसके दिनभर के कार्य सिद्धि की दिशा में बढ़ने लगते हैं।

जीवन के संघर्ष में जब मनुष्य घर से बाहर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलता है, तब उसका मन भय और अनिश्चितता से भरा होता है। ऐसे समय में तुलसी के तीन या चार पत्तों को ग्रहण करना शुभ माना गया है। तुलसी को "देवी स्वरूप" कहा गया है जो अपने संपर्क से सभी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करती है। कहा जाता है कि तुलसी का सेवन करने वाला व्यक्ति अदृश्य शक्ति से संरक्षित हो जाता है और उसके कर्म में आने वाली रुकावटें स्वतः मिट जाती हैं।

प्रातःकाल दीपक में दो फूल वाली अखंडित लौंग डालकर उसे भगवान के समक्ष जलाने का भी अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग बताया गया है। लौंग की सुगंध वातावरण को पवित्र करती है और घर की ऊर्जा को संतुलित करती है। जब व्यक्ति इस दीपक को देखकर घर से निकलता है तो उसके मन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है।

हर कार्य की सफलता में किसी जरूरतमंद का आशीर्वाद छिपा होता है। इसलिए घर से निकलते समय हाथ में एक निश्चित धनराशि लेकर किसी भिक्षुक को दान करने की परंपरा अत्यंत शुभ कही गई है।

दान से व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के दोष क्षीण होते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां उसके पक्ष में कार्य करने लगती हैं।

माता दुर्गा को नौ लाल पुष्प अर्पित करने का उपाय भी हर प्रकार की कार्य बाधा को नष्ट करने वाला माना गया है। दुर्गा शक्ति स्वयं "विघ्न विनाशिनी" हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से प्रतिदिन या मंगलवार और शुक्रवार के दिन उन्हें लाल पुष्प चढ़ाकर "या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता" का जप करे तो उसके कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं।

व्यापार या नौकरी में अड़चनें तब आती हैं जब व्यक्ति के प्रयासों पर ग्रह दोषों की छाया होती है। ऐसी स्थिति में पीपल के वृक्ष पर सफेद कपड़े की ध्वजा बांधना अत्यंत शुभ होता है। पीपल का वृक्ष स्वयं विष्णु स्वरूप है, और ध्वजा बांधने का अर्थ है अपने कर्म को ईश्वरीय संरक्षण में देना। यह उपाय शनि दोष से भी मुक्ति दिलाता है।

घर में शांति बनाए रखने और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए चावल और हल्दी को मिलाकर मुख्य द्वार पर 'ऊं' और 'स्वास्तिक' का चिह्न बनाना बहुत लाभदायक होता है। यह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक तरंगों को रोक देता है।

शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य ही जीवन का मूल है। सूर्य से व्यक्ति को आत्मबल, तेज और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए प्रतिदिन "आदित्य हृदय स्तोत्र" और "राम रक्षा स्तोत्र" का पाठ करने से जीवन के सभी भय और अवरोध समाप्त हो जाते हैं। ये स्तोत्र व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देते हैं, जो उसे विपत्तियों से बचाता है।

शुभ कार्य पर निकलते समय दही, गुड़ या मिठाई का सेवन करने की परंपरा केवल लोकविश्वास नहीं बल्कि एक गूढ़ संकेत है। दही शीतलता और संतुलन का प्रतीक है, गुड़ ऊर्जा और सकारात्मकता का। इनका सेवन मन को स्थिर और आत्मविश्वासी बनाता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है।

शनिवार के दिन सरसों के तेल या काली उड़द का दान शनि देव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। शनि ही कर्मफल दाता हैं। जो व्यक्ति निष्ठा से शनि की आराधना करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति अपनी जन्मकुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा को सही ढंग से समझे, तो उसके अनुसार किए गए उपाय और रत्न धारण अद्भुत परिणाम देते हैं। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश ग्रहों का विश्लेषण कर योग्य ज्योतिषाचार्य से उचित रत्न जैसे माणिक्य, पन्ना, पुखराज, नीलम या मोती धारण करने से जीवन में स्थायित्व और सफलता सुनिश्चित होती है। लेकिन यह रत्न तभी फल देता है जब उसे विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा कर धारण किया जाए।

जीवन की बाधाएं हमेशा बाहरी नहीं होतीं, कई बार वे भीतर की शंकाओं, भय और नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होती हैं। जब व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और आत्मविश्वास से भर जाता है, तो ग्रह भी उसके अनुकूल हो जाते हैं और परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। इसीलिए कहा गया है — "विश्वासं फलदं शाश्वतं।" जो व्यक्ति इन छोटे-छोटे उपायों को नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाता है, उसका भाग्य उसका साथ देने लगता है। विघ्न-बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, वे उसके संकल्प और श्रद्धा के सामने झुक जाती हैं। जीवन में जब हर दिशा से रास्ते बंद होते दिखें, तब यही उपाय अदृश्य रूप से नये मार्ग खोलते हैं और वही व्यक्ति जो पहले असहाय महसूस करता था, सफलता का प्रतीक बन जाता है। यही है आस्था की शक्ति और कर्म की सच्ची साधना।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

चक्रवात से गुजरात को बचाने वाले अमित अरोड़ा ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फिर किया कमाल, लौह पुरुष की 150वीं जयंती को बनाया ऐतिहासिक आयोजन

(जीएनएस)। अहमदाबाद। यह कहानी एक ऐसे अधिकारी की है जिसने अपनी मेहनत, सूझबूझ और अदम्य इच्छाशक्ति से दो बार इतिहास रचा — पहली बार तब जब गुजरात विनाशकारी चक्रवात 'बिपरजॉय' की चपेट में था, और दूसरी बार जब लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश की निगाहें 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर टिकी थीं। ये अधिकारी हैं 2012 बैच के आईएएस अमित अरोड़ा, जो आज न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश की नौकरशाही में एक मिसाल बन चुके हैं।

अमित अरोड़ा वर्तमान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर तैनात हैं। उनके नेतृत्व में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' यानी 31 अक्तूबर का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि इसे 'मिनी गणतंत्र दिवस' कहा जाने लगा। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, लौह पुरुष के परिवारजन और करीब 12,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। सुबह की एकता परेड से लेकर 'सूर्य किरण' विमानों के एअर शो तक, हर कार्यक्रम अनुशासन और गरिमा के साथ संपन्न हुआ — और इसका श्रेय जाता है अमित अरोड़ा की शांत लेकिन प्रभावी प्रशासनिक शैली को।

यह आयोजन आसान नहीं था। कार्यक्रम से कुछ दिन पहले से ही गुजरात में लगातार बेमौसम बारिश हो रही थी। 30 अक्तूबर को जब प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा पहुंचे, तो खराब मौसम के बावजूद वे सड़क मार्ग से केवडिया पहुंचे। हर किसी की नजर इस पर थी कि मौसम की मार कहीं समारोह पर न पड़ जाए, लेकिन अमित अरोड़ा ने अपनी टीम के साथ ऐसा बेहतरीन समन्वय किया कि न केवल सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुए,

बल्कि सुरक्षा और प्रबंधन के लिहाज से यह आयोजन एक मानक बन गया।

यह पहली बार नहीं था जब अमित अरोड़ा ने कठिन परिस्थितियों में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। जून 2023 में जब गुजरात के कच्छ जिले पर भीषण चक्रवात 'बिपरजॉय' ने दस्तक दी थी, तब अरोड़ा वहां कलेक्टर के रूप में तैनात थे। चक्रवात की तीव्रता ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक थी, लेकिन उनकी कुशल रणनीति और समय पर लिए गए निर्णयों की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया और बिजली, जलापूर्ति जैसी मूल सेवाओं को रिकॉर्ड समय में बहाल कर दिया गया। उस समय अरोड़ा पीजीवीसीएल (पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड) के ज्वाइंट एमडी भी थे और उन्होंने एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ऐसी टीमवर्क दिखाई कि पूरा देश उनकी सराहना करने लगा।

बरेली, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अमित अरोड़ा इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बी.टेक और एम.टेक की डुअल डिग्री प्राप्त की है। आईआईटी में रहते हुए ही उनमें नेतृत्व और संकट प्रबंधन के गुण उभरने लगे थे, जो बाद में प्रशासनिक सेवा में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। उनकी पत्नी प्रीति शर्मा भी उच्च शिक्षित हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं।

अपने अब तक के करियर में अरोड़ा ने गोधरा, राजकोट और वडोदरा जैसे कई संवेदनशील जिलों में काम किया है। राजकोट के नगर आयुक्त के रूप में उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, वहीं कच्छ में उनके कार्यकाल को 'संवेदनशील और दृढ़ नेतृत्व' का आदर्श उदाहरण कहा गया।

अरोड़ा के सहकर्मी उन्हें "लो प्रोफाइल लेकिन हाई परफॉर्मेंस" अफसर के रूप में जानते हैं। वह प्रचार से दूर रहते हैं लेकिन परिणामों से अपनी पहचान बनाते हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि वे हर काम को टीम भावना और तकनीकी दक्षता के साथ पूरा करते हैं। यही कारण है कि जब सरकार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को सौंपनी थी जो न केवल आयोजन की भव्यता को संभाल सके बल्कि सुरक्षा और मौसम जैसी अप्रत्याशित चुनौतियों का भी सामना कर सके, तब नाम आया — अमित अरोड़ा का।

अब जब सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह की भव्यता की चर्चा देशभर में हो रही है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस लौह पुरुष की मूर्ति के नीचे यह आयोजन हुआ, उसकी आत्मा शायद गर्व से मुस्कुरा रही होगी — क्योंकि इस बार आयोजन की कमान भी एक "लौह इच्छाशक्ति" वाले अधिकारी के हाथों में थी।

अमित अरोड़ा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संकट हो या उत्सव — अगर नेतृत्व दृढ़, विचार स्पष्ट और दृष्टि समर्पित हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है।

दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शरजील इमाम की किस्मत पर टिकी निगाहें

(जीएनएस)। नई दिल्ली। 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े बहुचर्चित मामले में आज एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत में हलचल मचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को छात्र नेताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू करेगा। इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गंभीर आरोप हैं, और यह सुनवाई इस बात पर तय करेगी कि उन्हें जेल से राहत मिलेगी या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉजलिस्ट के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ 3 नवंबर को सह-आरोपी मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान की याचिकाओं के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की दलीलें भी सुनेगी। यह सुनवाई लंबे समय से चल रहे इस मामले में अहम मोड़ मानी जा रही है।

पिछली सुनवाई में उमर खालिद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तीखी दलीलें दी थीं। उन्होंने कहा था कि प्रॉसिक्यूशन जानबूझकर ट्रायल में देरी कर रहा है और अब वह इसका ठीकरा आरोपी पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। सिब्बल

ने कहा था कि दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ी 751 एफआईआर में से केवल एक में उमर खालिद का नाम है, जबकि दंगे के दौरान वह दिल्ली में मौजूद भी नहीं थे। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि खालिद के पास से कोई आपत्तिजनक या अपराध सिद्ध करने वाला सामान नहीं मिला और उनके किसी भी कथित कार्य को यूएपीए के तहत "आतंकवादी गतिविधि" नहीं कहा जा सकता।

सिब्बल ने सह-आरोपियों आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के उदाहरण दिए, जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि अगर उन्हीं सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्हें बेल मिल सकती है, तो उमर खालिद को भी न्यायसंगत राहत मिलनी चाहिए।

दूसरी ओर, शरजील इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जांच पूरी नहीं की है और बार-बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शरजील इमाम को 25 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दंगे फरवरी में हुए थे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो व्यक्ति एक महीने पहले से जेल में है, वह दंगों में कैसे शामिल हो सकता है? दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल के भाषण दिसंबर 2019 में दिए गए थे, यानी दंगों से दो महीने पहले, और उन भाषणों में हिंसा या उकसावे का कोई उल्लेख नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दवे ने स्पष्ट किया कि शरजील ने केवल नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ शांतिपूर्ण चक्का जाम की अपील की थी, न कि किसी हिंसा का आह्वान किया था। इसी तरह गुलफिशा फातिमा की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उन पर सिर्फ विरोध स्थल बनाने का आरोप है, लेकिन उस स्थल पर किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि न तो मौखिक सबूत हैं और न ही कोई दस्तावेजी प्रमाण जो उन्हें साजिश से जोड़ते हों।

दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली यह सुनवाई न केवल इन छात्रों के भविष्य का फैसला करेगी, बल्कि देश में यूएपीए कानून के दुरुपयोग और संवैधानिक स्वतंत्रता के दायरे पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। अदालत की अगली कार्रवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि क्या अब इन आरोपियों को जेल मिलेगी या बेल।

भारत और बहरीन के रिश्तों में नई ऊर्जा, जयशंकर और अब्दुल लतीफ करेंगे उच्च संयुक्त आयोग की बैठक — 54 साल पुराने रिश्ते में नया अध्याय

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और बहरीन के बीच 54 वर्षों से चली आ रही कूटनीतिक मित्रता एक बार फिर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने जा रही है। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अलजयानी रविवार को भारत पहुंचे, जहां वे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ भारत–बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक न केवल दोनों देशों के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को फिर से पुष्ट करेगी, बल्कि व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर भी खोलेगी।

भारत और बहरीन के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी। लेकिन दोनों देशों के आपसी संपर्क इससे कहीं पहले के हैं — समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति ने इन संबंधों को समय के साथ और मजबूत किया है। बहरीन की खाड़ी में बसे भारतीयों का समुदाय वहां की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और दोनों देशों के बीच एक मजबूत मानवीय सेतु का कार्य करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "बहरीन साम्राज्य के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अलजयानी का भारत में स्वागत है। वे विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ पांचवीं भारत–बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। यह यात्रा हमारे संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।"

सूत्रों के अनुसार, बैठक के एजेंडे में व्यापार और निवेश को और गति देने, ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं की समीक्षा करने और नए आर्थिक साझेदारी मॉडल विकसित करने पर चर्चा होगी। खास तौर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी, फिनटेक (वित्तीय तकनीक), नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे।

भारत और बहरीन के बीच वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला हुआ है — जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रासायनिक उत्पाद और खाद्य पदार्थ शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेनदेन में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2024–25 के वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया।

बहरीन, खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक रणनीतिक साझेदार है। यह देश न केवल ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से अहम है, बल्कि भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य माना जाता है। करीब साढ़े तीन लाख भारतीय नागरिक बहरीन में रह रहे हैं, जो देश के श्रमबल, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि इस बैठक से भारत–बहरीन संबंधों में एक "क्वांटम जंप" देखने को मिल सकता है। यह बैठक दोनों देशों के बीच न केवल आर्थिक साझेदारी बल्कि रणनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को भी नया आयाम देगी।

डॉ. एस. जयशंकर और अब्दुल लतीफ बिन राशिद अलजयानी की बैठक से पहले दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा मामलों पर तकनीकी चर्चाएं भी कीं। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से कई महत्वपूर्ण समझौते और संयुक्त घोषणाएं सामने आएंगी, जो भारत और बहरीन के रिश्तों को "साझेदारी के नए युग" में प्रवेश दिलाएंगी।

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर में जनजातीय गौरव वर्ष उत्सव तथा भारत पर्व का भव्य शुभारंभ

▸▸ जनजातीय गौरव वर्ष उत्सव जनजाति समाज के गौरव को उजागर करने वाला उत्सव है : आदिजाति विकास राज्य मंत्री श्री पी. सी. बरंडा

▸▸ विषय विशेषज्ञों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र एवं संघर्ष गाथा तथा अमूल्य योगदान से अवगत कराया गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष उत्सव के हिस्से के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन एवं योगदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम उद्घाटन सत्र का टैंट सिटी-2 एकता नगर से प्रारंभ कराते हुए गुजरात सरकार के आदिजाति विकास राज्य मंत्री श्री पी. सी. बरंडा ने कहा कि जनजातीय समाज के गौरव को दर्शाने का यह उत्सव है। जल, जंगल व जमीन के साथ जनजातियों की अस्मिता व सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2021 से इस उत्सव की घोषणा की थी। वर्ष 2047 तक आदिजाति विकास को सुनिश्चित कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने रोड मैप तैयार किया है। विकसित भारत की बात जब आती है, तब गुजरात राज्य देश का रोल मॉडल बना है। आदिजाति समुदाय को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पशुपालन के साथ सभी क्षेत्रों में केन्द्र-राज्य सरकार ने परिणामदायी प्रयत्न किए हैं।

राष्ट्रीय स्तर के इस परिसंवाद के उद्घाटन सत्र के दौरान अध्यापकों-विद्यार्थियों की उपस्थिति में देश के विभिन राज्यों के विषय विशेषज्ञों ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन कार्य पर आधारित व्याख्यानों एवं शोध पत्रों की प्रस्तुति की तथा विचार-विमर्श किया। इसके अलावा, प्राध्यापक-शिक्षकों को कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

इस अवसर पर उदयपुर के सांसद श्री मन्नालाल रावत, भरूच के सांसद श्री मनसुखभाई वसावा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भीमसिंह तडवी, नांदोद की विधायक डॉ. दर्शनाबेन देशमुख, आदिजाति विकास विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती शाहमीना हुसैन, सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त श्री संजय प्रसाद, ओडिशा के सेवानिवृत्त टीआरआई निदेशक श्री ए. बी. ओटा, झारखंड-राँची आदिवासी कल्याण अनुसंधान संस्थान के श्री राजेन्द्र कुमार, बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉ. मधुकर पाडवी, आदिजाति विकास निदेशक श्री आशिष कुमार सहित उच्चाधिकारी, विषय विशेषज्ञ, अध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि 1 से 15 नवंबर, 2025 के दौरान एकता नगर में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र तथा संघर्ष गाथा प्रदर्शनी के माध्यम से उनके अमूल्य योगदान से विभिन्न राज्यों के पर्यटकों को अवगत कराया जाएगा।

इस अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष तथा भारत पर्व के उपलक्ष्य में आदिजाति परंपरा पिठोरा-वारली चित्रकला, आदिजाति कला संस्कृतिक की प्रदर्शनी, हस्तकला कृति की प्रदर्शनी, आदिवासी परंपरागत खाद्य उत्पादों, वाद्यों, वनौषधीय चिकित्सा प्राणियों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जाएगी। समग्र देश में बसने वाले आदिवासी समुदायों की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत जग विख्यात है। आदिवासियों की सामाजिक-सांस्कृतक विरासत को उजागर करने के लिए प्रतिदिन शाम को भव्य आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होने वाले हैं। गुजरात के विख्यात आदिवासी नृत्यों के माध्यम से आदिवासी सांस्कृतिक विरासत की प्रतीति कराई जाएगी।

15 नवंबर, 2025 यानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में समग्र राष्ट्र में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में विशाल जन समूह तथा गरिमामय महानुभावों की उपस्थिति में 15 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात के 151 स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तथा भगवान बिरसा मुंडा के यशस्वी जीवन चरित्र का वर्णन करने वाली पुस्तकों का महानुभावों के करकमलों से अनावरण किया जाएगा।

भारत की विकास यात्रा पर मंडरा रहा वैश्विक खतरा: मॉर्गन स्टैनली के मुख्य अर्थशास्त्री रिधम देसाई ने जताई चिंता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय अपनी सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। न केवल घरेलू निवेश में वृद्धि हो रही है बल्कि कंपनियों और परिवारों की बैलेंस शीट भी स्वस्थ है। सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार के कदमों ने विकास की रफ्तार को और तेज किया है। लेकिन, इसी मजबूत नींव के बीच एक गंभीर चेतावनी आई है — मॉर्गन स्टैनली के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट रिधम देसाई ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा भारत के भीतर नहीं, बल्कि सीमाओं के बाहर से है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि "भारत के लिए बहुत कुछ गलत हो सकता है, और इनमें से ज्यादातर चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर हैं।" देसाई ने बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई समिट में बोलते हुए कहा कि भारत के भीतर आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत है। कॉर्पोरेट सेक्टर का कर्ज घटा है, निवेश माहौल सुधरा है और घरेलू खपत में निरंतर वृद्धि हो रही है। लेकिन वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। उनका कहना है कि "दुनिया रिकॉर्ड स्तर के कर्ज, घटती जनसंख्या और अनिश्चित भू-राजनीतिक तनावों का सामना कर रही है। यह तीनों मिलकर वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं, जिसका सीधा असर भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ सकता है।"

रिधम देसाई ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। उन्होंने कहा, "जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, भारत जवान है। हमारे पास श्रमशक्ति है, उपभोग क्षमता है और मांग पैदा करने की शक्ति है। रोबोट उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन वे उपभोक्ता नहीं बन सकते। दुनिया को उपभोक्ता भारत में मिलेंगे — यही हमारी सबसे बड़ी आर्थिक ढाल है।"

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दो दशकों में भारत वैश्विक विकास में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी देगा। "अगले 10 से 20 सालों में भारत वैश्विक विकास का पांचवां हिस्सा बनेगा। जो कंपनियां अभी भारत में नहीं हैं, वे भविष्य में पछताएंगी," देसाई ने कहा। लेकिन देसाई ने इस आशावाद के बीच एक गहरी चिंता भी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत का भौगोलिक परिवेश चुनौतीपूर्ण है। "हम अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकते, लेकिन हमारे अधिकतर पड़ोसी या तो आर्थिक रूप से अस्थिर हैं या राजनीतिक संकट में हैं। यह स्थिति हमेशा भारत के लिए किसी न किसी रूप में खतरा बन सकती है," उन्होंने कहा।

घरेलू मोर्चे पर उन्होंने कृषि क्षेत्र को भारत की सबसे बड़ी अधूरी कहानी बताया। "भारत के पास करीब 20 करोड़ किसान हैं, जिनकी उत्पादकता दुनिया के औसत से बहुत नीचे है। अगर हम चीन जैसी उत्पादकता हासिल कर लें तो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। हमारे पास 35 करोड़ एकड़ कृषि भूमि है — यह दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। हम चाहें तो आधी दुनिया को अनाज खिला सकते हैं," उन्होंने कहा। देसाई ने जोर दिया कि कृषि सुधारों को फिर से जीवित करने की जरूरत है, ताकि किसानों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को विकास की मुख्यधारा में नहीं लाया गया तो बाकी आबादी के मुकाबले उनका पिछड़ना सामाजिक असंतुलन का कारण बन सकता है।

अपने संबोधन के अंत में देसाई ने कहा कि भारत की मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिति मजबूत और लचीली है, लेकिन वैश्विक जोखिम इसे झकझोर सकते हैं। "भारत तैयार है, लेकिन दुनिया कमजोर हो रही है। कर्ज के बोझ और घटती आबादी की दिशा में जा रही दुनिया किसी बड़े वित्तीय संकट को जन्म दे सकती है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा," उन्होंने कहा। इस तरह, देसाई का संदेश साफ था — भारत को अपने घरेलू सुधारों की गति बनाए रखनी होगी, लेकिन साथ ही उसे वैश्विक हलचलों पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में भारत की मजबूती का असली इम्तिहान सीमाओं के बाहर से होगा।

उत्कृष्ट टिकट जांच कार्य के लिए सम्मान

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा सभी वैध यात्रियों को सुगम, आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वडोदरा मंडल के मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में बिना टिकट/अनियमित यात्रियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर गहन टिकट जांच चलाए जा रहे हैं।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार टिकट जांच दलों द्वारा विभिन्न ट्रेनों एवं स्टेशनों पर टिकट जांच दवारा अक्टूबर माह में 8 टिकट जाँच कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

श्री सक्सेना ने बताया कि मंडल के वाणिज्य विभाग के टिकट चेकिंग स्टाफ श्री डी वी चौधरी, श्री पी के झा, श्री सुनिल पंडीर,श्री शैलेन्द्र क्षत्रिय , श्री एच जे लोटिया, श्री पी एस चौहान, श्रीमती भुमिका पटेल एवं

श्री रतिलाल वसावा को अक्टूबर माह में टिकट चेकिंग में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। श्रीमती भुमिका पटेल ने टिकट चेकिंग में अनियमित मामले की जांच कर एक दिन की सबसे अधिक आय अंकित की।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वडोदरा ने सभी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य एवं समर्पण के लिए सराहा और कहा कि यात्रियों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

बेमौसम बारिश से कृषि फसलों को हुए नुकसान पर शीघ्र ही राहत पैकेज घोषित करेगी राज्य सरकार

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बारिश के कारण किसानों की खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। इस अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के समय में राज्य सरकार पूरी संवेदना के साथ किसानों के साथ खड़ी है।

श्री पटेल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा, "राज्य के मंत्रियों ने विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का प्रत्यक्ष दौरा कर किसानों की स्थिति जानी है। प्रशासन द्वारा फसल को हुए नुकसान की समीक्षा तथा सर्वेक्षण का कार्य अत्यंत तेजी से शुरू किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में निरंतर मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय में हूँ।"

उन्होंने कहा कि धरतीपुत्रों के हित को

सर्वोच्च प्राथमिकता देकर राज्य सरकार किसानों को इस नुकसान में सहायक होने के लिए शीघ्र ही राहत-सहायता पैकेज घोषित करेगी।

ग्रो आईपीओ को लेकर उत्साह चरम पर, 4 नवंबर से खुलेगा सब्सक्रिप्शन—कंपनी ने तय किया 95-100 का प्राइस बैंड, 61,700 करोड़ की वैल्यूएशन का लक्ष्य

(जीएनएस)। नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए नवंबर का पहला हफ्ता बेहद अहम साबित होने जा रहा है। देश के लोकप्रिय ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म Groww की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड ने अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ (Initial Public Offering) की पूरी डिटेल्स जारी कर दी हैं। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 95 से 100 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है और बाजार से लगभग 6,632 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

यह आईपीओ 4 नवंबर को आम निवेशकों के लिए खुलेगा और 7 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। वहीं, एंकर निवेशकों के लिए बुक 3 नवंबर को खुलेगी। निवेशकों में पहले से ही इस इश्यू को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मार्केट विश्लेषकों के मुताबिक, ग्रो के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) फिलहाल 11 पर चल रहा है, जो इसके ऊपरी प्राइस बैंड 100 के मुकाबले लगभग 11% प्रीमियम दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि ग्रे मार्केट में ग्रो का शेयर 111 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो संकेत देता है कि लिस्टिंग के दिन निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि जीएमपी में उतार-चढ़ाव लिस्टिंग तक बना रहेगा। कंपनी ने बताया कि आईपीओ में 55.72 करोड़ शेयर मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे, जबकि 1,060 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इस पूंजी का इस्तेमाल कंपनी अपने ब्रांड को और मजबूत करने, नई तकनीकी परियोजनाओं में निवेश, और नए वित्तीय उत्पादों की शुरुआत के लिए करेगी। ग्रो के को-फाउंडर हर्ष जैन ने कहा कि कंपनी लगातार तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करती रही है और आने वाले समय में इसे और गति देने की योजना है।

‘तेजस्वी बने तो बनेंगे तीन नए विभाग – अपहरण, रंगदारी और खून’; बिहार में पीएम मोदी की सभा में गूंजा ‘जंगलराज’ का मुद्दा

(जीएनएस)। मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक तापमान अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मुजफ्फरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर लालू-राबड़ी परिवार के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो बिहार में तीन नए विभाग बन जाएंगे — “अपहरण विभाग”, “रंगदारी विभाग” और “खून विभाग।” मोदी ने कहा कि यह वही बिहार है जिसने कभी जंगलराज की भयावहता झेली थी, और अब वही ताकतें फिर से सत्ता में लौटने का सपना देख रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मुजफ्फरपुर के कुख्यात गोलू हत्याकांड से की, जिसने वर्ष 2001 में पूरे राज्य को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा, “गोलू जैसे मासूम बच्चों की हत्या की याद आज भी बिहार के लोगों के दिल में जख्म की तरह ताजा है। उस दौर में कानून का राज नहीं, बल्कि अपराधियों का शासन चलता था। फिरौती के लिए अपहरण, हत्या और रंगदारी उस समय का आम चलन था।” मोदी ने यह भी याद दिलाया कि गोलू हत्याकांड के विरोध में जब जनता सड़कों पर उतरी थी, तब पुलिस की गोलीबारी में सात लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा, “आज मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने न्याय के लिए अपनी जान दी, और बिहार को फिर कभी जंगलराज में लौटने से रोकने की कसम खाई।”

इसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने साहेबगंज विधानसभा के देवरिया में चुनावी रैली कर जंगलराज की तस्वीर को और गहराई से सामने रखा। उन्होंने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की नृशंस हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि “वह दौर ऐसा था जब अफसर भी अपराधियों से सुरक्षित नहीं थे। और आज वही परिवार

फिर से सत्ता में लौटना चाहता है।” शाह ने तीखे अंदाज में कहा, “अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो बिहार में तीन नए मंत्रालय खुलेंगे — अपहरण उद्योग मंत्रालय, रंगदारी संग्रह मंत्रालय और खून-खराबा विभाग। इनके मंत्री भी तय होंगे, और हर गली में अपराध की सरकार लौट आएगी।”

पीएम मोदी और अमित शाह, दोनों के भाषणों में “जंगलराज” शब्द की लगातार गूंज रही। यह स्पष्ट संकेत था कि एनडीए की रणनीति इस चुनाव में कानून-व्यवस्था और शासन की स्थिरता को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की है। मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार का लक्ष्य बिहार को “बाढ़ से मुक्त, भय से मुक्त और भ्रष्टाचार से मुक्त” बनाना है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार और एनडीए की साझेदारी ने बिहार को पिछड़ेपन से निकालकर विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है।

अमित शाह ने अपने संबोधन में धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के मुद्दों को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि “पीएम मोदी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनवाया और अब सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। बहुत जल्द अयोध्या से सीतामढ़ी को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार का पर्यटन नई ऊंचाई पर पहुंचेगा।” उन्होंने मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों — बाबा गरीबनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और बगलामुखी मंदिर — का भी उल्लेख किया और कहा कि “यह भूमि सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि बलिदान की भी भूमि है।” अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानियों और बिहार के नायकों को याद करते हुए कहा, “अमर शहीद खुदीराम बोस, जुब्बा सहनी, पंडित सहदेव झा, लंगट सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जय नारायण निषाद ने इस धरती को गौरव दिया है। आज मोदी सरकार उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है।” उन्होंने यह भी बताया कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मोदी सरकार ने जीआई टैग दिलाया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही लीची उत्पादों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने से राज्य के बागवानों को राहत मिली है।

वकील और एडवोकेट में बड़ा अंतर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—कंपनी के ‘इन-हाउस वकील’ एडवोकेट नहीं, अटॉर्नी-क्लाइंट प्रिविलेज का अधिकार नहीं मिलेगा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कानूनी पेशे की परिभाषा को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कंपनी के अंदर काम करने वाले वकील—जिन्हें ‘इन-हाउस काउंसल’ या ‘कॉरपोरेट लॉयर’ कहा जाता है—भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत “एडवोकेट” की श्रेणी में नहीं आते। इस फैसले के साथ अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे वकीलों को अटॉर्नी-क्लाइंट प्रिविलेज (गोपनीय संचार का अधिकार) नहीं मिलेगा, क्योंकि वे अदालतों में स्वतंत्र रूप से कानून का अभ्यास नहीं करते।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन भी शामिल थे, ने यह फैसला सुनाया। यह मामला तब उठा जब जांच एजेंसियों ने कुछ कॉर्पोरेट वकीलों को उनके क्लाइंट्स के साथ हुई गोपनीय बातचीत के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया था। अदालत ने इस पर कहा कि “प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन” यानी गोपनीय वकील-मुवक्किल संवाद के बारे में जांच एजेंसियां पूछताछ नहीं कर सकतीं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि “हर लॉ की डिग्री रखने वाला व्यक्ति एडवोकेट नहीं होता।”

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो लोग किसी कंपनी में वेतनभोगी रूप में काम करते हैं—चाहे वे कानूनी सलाहकार हों या इन-हाउस वकील—वे एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की परिभाषा के अनुसार “वकील” नहीं माने जा सकते। जस्टिस चंद्रन ने कहा, “इन-हाउस वकीलों का नियमित रोजगार और पूर्ण वेतन उन्हें एडवोकेट्स एक्ट में बताए गए स्वतंत्र वकील की श्रेणी से अलग करता है। वे अदालतों में प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए वे BSA की धारा 132 के तहत विशेषाधिकार के पात्र नहीं हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 2(a), 29 और 33 का हवाला देते हुए कहा कि केवल वही व्यक्ति “एडवोकेट” कहलाता है जिसका नाम किसी राज्य बार काउंसिल की सूची में दर्ज हो और जो अदालतों, न्यायाधिकरणों या अन्य प्राधिकरणों के सामने कानून का अभ्यास करने का अधिकार रखता हो। वहीं “लॉयर” शब्द सामान्य रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो, भले ही वह कानूनी सलाह दे, अनुबंध तैयार करे या कानून पढ़ाए—लेकिन जब तक वह बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं है, वह अदालत में पेश नहीं हो सकता।

फैसले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 49 का भी उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अदालत ने कहा, “वकालत एक पेशा है, नौकरी नहीं। वकालत स्वतंत्र निर्णय, नैतिक स्वतंत्रता और अदालत के प्रति निष्ठा पर आधारित होती है—ये सब तब प्रभावित हो जाते हैं जब वकील किसी कंपनी के पदानुक्रम या व्यावसायिक हितों के अधीन होता है।” यह फैसला कानूनी पेशे में एक लंबे समय से चल रहे भ्रम को दूर करता है, जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में कानूनी सलाहकारों की बढ़ती भूमिका ने ‘लॉयर’ और ‘एडवोकेट’ के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह स्पष्ट किया है कि केवल वही व्यक्ति, जो बार काउंसिल में नामांकित है और अदालत में पेश हो सकता है, “वकील” (Advocate) कहलाएगा और वही अपने मुवक्किल के साथ किए गए संचार के लिए अटॉर्नी-क्लाइंट प्रिविलेज का हकदार होगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल कॉर्पोरेट कानूनी ढांचे में स्पष्टता आएगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अब इन-हाउस वकीलों को अपने कॉर्पोरेट नियोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व और कानूनी प्रैक्टिस के नैतिक दायित्वों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से समझना होगा।

एक करोड़ रोजगार सिर्फ वादा नहीं, हमारा संकल्प : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

(जीएनएस)। आरा। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा की ऐतिहासिक भूमि से एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत की। उत्साहित जनसमूह के बीच उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और कहा कि “एक करोड़ रोजगार देने का वादा सिर्फ राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि राजग सरकार का ठोस संकल्प है, जिसे पूरा करने की विस्तृत योजना तैयार है।” उन्होंने कहा कि अब बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा — अब बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा और राज्य के गौरव को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित बिहार ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। बिहार की प्रगति के बिना भारत का सर्वांगीण विकास अधूरा रहेगा।

उन्होंने कहा कि राजग सरकार का विज़न औद्योगिक विस्तार, आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्थायी रोजगार सृजन पर केंद्रित है। मोदी ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में बिहार को आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और युवा-सशक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि “राजग का घोषणापत्र विश्वास और विकास का प्रतीक है, जबकि विपक्ष का घोषणापत्र केवल झूठ और छलावे से भरा हुआ कागज़ है।” उन्होंने कहा कि जंगलराज लाने वाले अब फिर से सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है। “ये जनता भगवान जैसी है — सब देखती है, सब समझती है, मगर धोखा किसी को नहीं देती।”

तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया गया। उन्होंने कहा कि जिनके बीच चुनाव से पहले ही आपसी झगड़े हैं, वे चुनाव के बाद बिहार का क्या हाल करेंगे, यह जनता भलीभांति जानती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजग का संकल्प ‘युवा सशक्त, बिहार समृद्ध’ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार को उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। मोदी ने जनता से आह्वान किया कि वे इस मिशन को सफल बनाने के लिए एनडीए को एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाएँ, क्योंकि “विकसित बिहार ही विकसित भारत का भविष्य है।”

त्रिशूल : तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास पश्चिमी मोर्चे पर — नेवी नेतृत्व में नौ दिन का बहु-डोमेन अभ्यास शुरू, इंस्टा-विक्रम, वॉरशिप और 25 हजार सैनिक होंगे तैनात

(जीएनएस)। नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारतीय थल, नौ तथा वायु सेनाओं का एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास अगले चरण में उतर गया है। नेवी के नेतृत्व में चलने वाला यह विशाल अभ्यास—जिसे ‘त्रिशूल’ नाम दिया गया है—तीन नवंबर से शुरू हो रहा है और लगभग दस दिनों तक पश्चिमी सीमाओं, गुजरात तट व उत्तर अरब सागर में चलने की योजना है। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य ट्राई-सर्विस तालमेल को मज़बूत करना, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स की प्रैक्टिस करना और स्वदेशी प्लेटफॉर्म तथा प्रणालियों के साथ वास्तविक-पर्याप्ति पर युद्ध संचालन की क्षमता का परीक्षण करना है। वेस्टर्न नेवल कमांड मुख्यालय से समन्वित इस अभ्यास में इंडियन आर्मी के साउदर्न कमांड, इंडियन नेवी के वेस्टर्न कमांड और इंडियन एयर फोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड मुख्यतः शामिल हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अन्य केंद्रीय एजेंसियाँ भी सुनियोजित हिस्सेदारी निभाएँगी। अभ्यास के दौरान राजस्थान व गुजरात के क्रीक, रेगिस्तानी इलाकों और उत्तर अरब सागर में साथ-साथ समुद्री, एंफीबियस तथा तटीय ऑपरेशंस कराये जाएँगे जिससे फ्लैट, रेगिस्तान तथा समुद्री परिदृश्यों में एकसमान युद्ध-प्रवेणता जाँची जा सके।

समन्वय केन्द्र ने बताया कि त्रिशूल में बड़ी संख्या में नेवी वॉरशिप, एयरफोर्स के फाइटर जेट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट, आर्मी के पैराट्रूपर, मैकेनाइज़्ड यूनिट और स्पेशल कमांडो हिस्सा लेंगे। नेवी के लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक आईएनएस जलश्वा तथा लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल का उपयोग भी एंफीबियस ऑपरेशंस में किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अपने पूरे कैरियर बैटल ग्रुप सहित अभ्यास का हिस्सा होगा, जबकि कुल 20 से 25 युद्धक जलयान तैनात रहेंगे। वायु घटक में करीब 40 लड़ाकू विमान—राफेल, सुखोई सहित—हेलीकॉप्टर और लाइट एहतियाती एयरक्राफ्ट शमिल होंगे। थल सेना से भी लगभग दो कोर यानी करीब 25 हज़ार सैनिक विभिन्न परिदृश्यों में तैनात रहेंगे और आधुनिक स्वदेशी हथियारों तथा प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाएगा।

त्रिशूल का ड्राइव-फोकस केवल प्लेट-फॉर्म नहीं, नेटवर्क और इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन पर है। अभ्यास जॉइंट इंटेलिजेंस, सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर-ऑपरशंस के संयोजन को परखेगा ताकि वास्तविक

स्थिति में सभी डोमेनों का समन्वय अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके। नियंत्रण-कक्षों में मल्टी-डोमेन कमांड-एंड-कंट्रोल की प्रक्रियाएँ परखी जाएँगी और सेक्टर-स्तर पर डेटा-शेयरिंग, लक्ष्य-नियंत्रण और त्वरित निर्णय-प्रक्रिया पर विशेष ध्यान होगा। यह अभ्यास नेवी-मेजरिटी पर होने के बावजूद तीनों सेवाओं के बीच वास्तविक समय पर संचार और ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी पर जोर देगा। रक्षा सूत्रों ने कहा कि अभ्यास का एक लक्ष्य स्वदेशी क्षमताओं का जमीनी परीक्षण भी है। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, फ्लोटिंग सपोर्ट, हाइ-इंटेन्सिटी एम्फिबियस-लैंडिंग और तटीय रक्षा-परिदृश्यों में स्वदेशी प्रणालियाँ किस हद तक सक्षम हैं, इसका आकलन किया जाएगा। साथ ही असिमेट्रिक खतरों—जैसे ड्रोन-आधारित निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और साइबर हमला—के विरुद्ध जॉइंट डिफेंस मेकानिज्म पर भी जोर होगा। अभ्यास के दौरान ह्यूमन रेस्क्यू, मेडिकल एविडेंस-शेयरिंग और आपदा प्रबंधन के सीनारियो भी शामिल किए गए हैं ताकि मल्टी-एजेंसी प्रतिक्रिया को भी परखा जा सके। गुजरात तट तथा उत्तर अरब सागर में किए जाने वाले अभ्यास से समुद्री रूट्स की सुरक्षा, तटीय निगरानी और समुद्री डोमेन अवेयरनेस (MDA) को बढ़ाने का उद्देश्य है। नौसेना-नेतृत्व वाले इन परिदृश्यों में समुद्री आक्रमण-रोधी, एंफिबियस असॉल्ट-रिजाइम्स और समुद्री सतह-से-हवा तालमेल के अभ्यास होंगे। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह पर्व समुद्री-क्षेत्र में भारत की हड़ताल-क्षमता तथा चोट-रहित रक्षा-तंत्र दोनों को परखने का अवसर देगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्रिशूल कोई आक्रामक पहल नहीं बल्कि एक तैयारी-उन्मुख अभ्यास है, ताकि किसी संकट-स्थिति में त्वरित, संगठित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। अभ्यास की योजना और समय-निर्धारण को लेकर विशेष रूप से संचार की पारदर्शिता बरती जा रही है ताकि क्षेत्रीय शांति-स्थिरता बनी रहे और किसी गलतफहमी से बचा जा सके। इसी महीने पूर्वी सीमाओं पर भी एक ट्राई-सर्विस अभ्यास मेचुका (अरुणाचल प्रदेश) में आयोजित किया जाएगा जिसका नाम ‘पूर्वी प्रचण्ड प्रहार’ रखा गया है; वहां पर्वतीय, हवाई और नदी/नदीनुमा परिदृश्यों में स्पेशल-फोर्सेज और ड्रोन-डेटाबेस का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होगा। अभ्यास के आयोजन से स्थानीय प्रशासन और सिविल संस्थाओं के साथ समन्वय भी आवश्यक है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि रूट-सेक्योरिटी, तटीय-ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिविल-आकस्मिक सेवाओं के साथ तालमेल पहले से स्थापित किया गया है। समुद्री और तटीय गतिविधियों के लिए NOTAMs (नोटिस टू एअर मैन), नेविगेशन वॉर्निंग और स्थानीय चेतावनियाँ जारी की गई हैं ताकि व्यापारिक और मछुआरा-जहाजों को रूट बदलने या सतर्क रहने की सूचनाएँ मिलें। रणनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि त्रिशूल जैसी अभ्यास-श्रृंखलाएँ भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त क्षमता को और उन्नत कर रही हैं और सीमाओं पर युद्ध-तैयारी के साथ-साथ दमन-रहित सन्दर्भ में रक्षा-नीति के संरक्षण में भी सहायक होंगी। अभ्यास की समाप्ति के बाद दोनों सेनाएँ आपसी सीख और प्रक्रियाओं का विस्तृत ऑडिट करेंगी तथा आवश्यक पाठों (lessons learned) को अगले प्रशिक्षण-सत्रों में समाहित करेंगी। त्रिशूल का यह चरण न केवल तकनीकी दक्षता की कसौटी होगा, बल्कि समन्वित कार्रवाई, निर्णय-गति और कमांड-सिन्योरिटी का भी परखने वाला व्यायाम साबित होगा। रक्षा महानिदेशालय ने यह सुनिश्चित किया है कि अभ्यास के दौरान सभी नियमों का पालन होगा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाये रखने के लिए आवश्यक पारदर्शिता और समन्वय जारी रहेगा।

हिंदू अपनी संस्कृति का करें संरक्षण : जगद्गुरु रामभद्राचार्य

(जीएनएस)। फतेहपुर। भगवान जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन समारोह में पहुंचे पद्मविभूषण पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि हिंदू समाज को अपनी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए सजग और संगठित होना होगा। शनिवार को फतेहपुर के पक्का तालाब स्थित मंदिर प्रांगण में उड़ीसा के दैतापति महाराज सहित अनेक संतों, साधु-संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में उन्होंने मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी।

भव्य आयोजन में पहले पूजन के पश्चात जगद्गुरु ने स्वयं प्रथम फावड़ा चलाकर मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति के पुनर्जागरण की दिशा में एक पवित्र संकल्प है।

स्वामी रामभद्राचार्य ने इस अवसर पर कहा कि भारत की आत्मा उसकी सनातन संस्कृति में बसती है। यदि हिंदू समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, तभी देश की आध्यात्मिक पहचान सुरक्षित रह पाएगी। उन्होंने कहा कि संस्कृति का संरक्षण ही राष्ट्र की सच्ची सेवा है और यह जिम्मेदारी हर हिंदू को अपने जीवन का लक्ष्य बनानी चाहिए।

उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से कहा कि आज के समय में शिक्षा के माध्यम से सनातन ज्ञान का प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक व भाजपा नेता संतोष तिवारी से आग्रह किया कि वे हिंदू बच्चों के लिए एक ऐसा विद्यालय स्थापित करें, जहाँ उन्हें भारतीय संस्कृति, धर्मग्रंथों और परंपराओं का गहन अध्ययन कराया जा सके। इस पहल के लिए उन्होंने मंच से चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की और समाज के अन्य लोगों से भी सहयोग का आह्वान किया।

जगद्गुरु ने अंत में कहा कि जब हिंदू समाज एकजुट होकर अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा होगा, तभी भारत अपनी वास्तविक पहचान के साथ विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित होगा।

चार दिग्गज कंपनियों के मार्केट कैप में 95 हजार करोड़ की बढ़ोतरी, रिलायंस ने फिर मारी बाजी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के शेयर बाजार में बीते कारोबारी हफ्ते के दौरान उतार-चढ़ाव भरे माहौल के बावजूद कुछ कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सप्ताह के अंत में देश की टॉप 10 कंपनियों में से चार कंपनियों — रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), भारती एयरटेल और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) — के मार्केट कैप में कुल 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, बाकी छह प्रमुख कंपनियों के मूल्य में लगभग 91 हजार करोड़ रुपये की गिरावट आई। सबसे बड़ी बढ़त रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिली। कंपनी के शेयरों में निवेशकों का भरोसा कायम रहा और इसका मार्केट कैप 47,431 करोड़ रुपये उछलकर 20.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस उछाल के साथ रिलायंस एक बार फिर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में शीर्ष पर बनी रही। भारतीय स्टेट बैंक ने भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए अपने मार्केट कैप में 30,091 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की और यह 8.64 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। भारती एयरटेल को 14,540 करोड़ रुपये का लाभ हुआ, जिससे इसका कुल मूल्य 11.71 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, भारतीय

जीवन बीमा निगम (LIC) के मार्केट कैप में 3,383 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज हुई और यह 5.65 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, यह हफ्ता सभी कंपनियों के लिए सुखद नहीं रहा। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट देखी गई। सबसे बड़ी गिरावट बजाज फाइनेंस में दर्ज हुई, जिसका मार्केट कैप 29,090 करोड़ रुपये घटकर 6.48 लाख करोड़ रुपये रह गया। आईसीआईसीआई बैंक में 21,618 करोड़ रुपये, इंफोसिस में 17,822 करोड़ रुपये, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 11,924 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक में 9,547 करोड़ रुपये और टीसीएस में 1,682 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। मार्केट वैल्यू के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज 20.11 लाख करोड़ रुपये के साथ शीर्ष पर है, जबकि उसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी क्रमशः शीर्ष दस कंपनियों में शामिल हैं। बीते हफ्ते बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयरों में हल्की अस्थिरता देखी गई, लेकिन रिलायंस और बैंकिंग शेयरों की मजबूती ने निवेशकों को उम्मीद की किरण दी है कि आने वाले हफ्तों में बाजार फिर से नई ऊंचाई छू सकता है।

‘बाहुबली’ रॉकेट से उड़ान भरता भारत का सबसे भारी सैटेलाइट जीसैट 7आर, नौसेना को मिलेगा आसमान से महासागर तक अदृश्य कवच

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत ने रविवार को अंतरिक्ष इतिहास का एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया जब इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) ने अपने ‘बाहुबली रॉकेट’ के जरिए अब तक का सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह जीसैट-7आर (GSAT-7R / CMS-03) सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसरो की यह उपलब्धि सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान की नहीं, बल्कि देश की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है।

करीब 4,400 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वह न सिर्फ धरती पर, बल्कि अंतरिक्ष से भी अपने समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है।

जीसैट-7आर, भारतीय नौसेना के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया एक उन्नत कम्युनिकेशन और सर्विलांस

सैटेलाइट है। यह नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और समुद्री कमांड सेंटर्स को एक सुरक्षित और निर्बाध संचार नेटवर्क में जोड़ेगा। इसके जरिए हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में रीयल टाइम डेटा ट्रांसमिशन, वीडियो लिंक और हाई-स्पीड वॉयस कम्युनिकेशन संभव हो सकेगा।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह सैटेलाइट भारत की ‘नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर’ क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। अब नौसेना के बेड़े चाहे अरब सागर में हों या बंगाल की खाड़ी में — सभी जहाज एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। इससे किसी भी आकस्मिक स्थिति में तेज निर्णय लेने और समन्वित कार्रवाई संभव होगी। इस सैटेलाइट में लगे उन्नत ट्रांसपोंडर विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम कर सकते हैं, जिससे यह लंबी दूरी पर भी स्थिर संचार बनाए रखता है। खास बात यह है कि यह सिग्नल जामिंग या हैकिंग से बचाने के लिए एन्क्रिप्टेड नेटवर्किंग सिस्टम से लैस है। यानी दुश्मन चाहे तकनीकी रूप से कितना भी उन्नत क्यों न हो, भारतीय नौसेना का संवाद सिस्टम अभेद्य रहेगा।

जीसैट-7आर को ‘रुक्षक सैटेलाइट’ कहा जा रहा है, क्योंकि यह भारतीय महासागर क्षेत्र में हर पल निगरानी रखेगा और दुश्मन की किसी भी गतिविधि का त्वरित अलर्ट भेज सकेगा। यह प्रणाली नौसेना की Maritime Domain Awareness (MDA) को और सशक्त बनाएगी, जिससे दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों या ड्रोन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी।

यह मिशन इसरो के लिए भी ऐतिहासिक है। इसके प्रक्षेपण में जिस रॉकेट का उपयोग किया गया, उसे वैज्ञानिकों ने ‘बाहुबली रॉकेट’ कहा है — क्योंकि यह अत्यधिक भारी भार को अंतरिक्ष की ऊँचाई तक ले जाने में सक्षम है। इस रॉकेट के सफल संचालन से इसरो ने दिखाया है कि भारत अब अंतरिक्ष तकनीक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों की पंक्ति में मजबूती से खड़ा है।

यह सैटेलाइट न केवल भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियानों को भी नई ऊर्जा देगा। इसकी सफलता यह संदेश देती है कि भारत अब अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा।

रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि जीसैट-7आर की तैनाती से भारत की नौसेना “डिजिटल नेवी” की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुकी है। अब समुद्री सीमाओं पर गश्त, मिशन कंट्रोल, निगरानी, और सामरिक संचार—सभी अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीक से जुड़े होंगे। यह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक बढ़त को मजबूत करेगा, बल्कि किसी भी संभावित खतरे का जवाब अब अंतरिक्ष से भी दिया जा सकेगा।

एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी के शब्दों में — “जीसैट-7आर हमारे लिए आसमान में वह आंख है जो कभी नहीं झपकती। यह भारत की समुद्री सुरक्षा को नए युग में प्रवेश दिलाने वाला उपग्रह है।”

इसरो की यह उड़ान न केवल विज्ञान की जीत है, बल्कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले हर नौसैनिक के आत्मविश्वास की भी उड़ान है — और यह उड़ान अब रुकने वाली नहीं।